SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Sir, the workers are suffering a. lot because the agreement which is there is not implemented. The hon. Minister promised to us to implement it.

MR. CHAIRMAN; We have moved to question No. 224. We have already spent 52 minutes on three questions. Question No. 224.

Delinking of J and K from census

*224. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that state of Jammu and Kashmir was delinked from the census held early this year;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) by when Government propose to undertake census in that State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB)-

(a) Yes, Sir.

(b) Separate date, for conducting the census in Jammu and Kashmir state were fixed in consultation with the State Government keeping in view the weather conditions in various parts of the State.

(c) The field situation is not con ducive to holding of the 1991 census in Jammu and Kashmir State. How ever, in J and K in 1986-87, a mini-census based on house to house enu meration was conducted on the lines of a decennial census. Data collected is proposed to be utilised for prepar ing the projected population of J and K State in 1991.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : सभापति जी मंत्री महोदय ने इस प्रश्न के उत्तर में स्वयं ही परस्पर विरोधी बातें कहीं हैं। पहले उन्होंने यह कहा है कि जम्मू-कश्मीर में वहां की मौसम की स्थिति के कारण से वहां हम जन-गणना नहीं कर सके।

जो दूसरे पैरा में वह कहते हैं कि वहां की क्षेत्रीय परिस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम जन-गणना नहीं कर सके, इन दोनों में से परस्पर विरोध व्यक्त हो रहा है। यह एक बात है।

दूसरी बात यह है कि सारी जन-गणना सारे देश में हुई है। मैं नहीं समझता कि कोई विशेष वहां का मौसम है, जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है और जम्मू-कश्मीर में है और जिसके कारण जन-गणना वहां पर स्थगित की गई।

मैं समझता हूं कि गृह मंत्री महोदय शायद कल जो हमारे दूसरे हाऊस में रिलीजस प्लेसस पर बिल पास हुआ है और वह जम्मू-कश्मीर पर एक्सटेंड नहीं हो रहा है, तो वह शायद इसका उत्तर देते कि वहां का मौसम देखते हुए हम वहां पच इंप्लिमेंट नहीं कर सके।

मैं यह जानना चाहता हूं, सरकार के इस उत्तर से, कि क्या जन-गणना को स्थगित करने के लिए यह आवेदन प्रदेश सरकार ने किया? आपने जो कहा है कि प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके कोई इसमें से हमने और तिथियां बदलने का फैसला किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह आवेदन प्रदेश सरकार ने किया? केन्द्र और प्रदेश सरकार के किस स्तर पर परामर्श होकर यह तय हुआ और जनगणना के लिए अगली तिथि कौन सी तय हुई? क्योंकि इसमें आपने यह कहा है कि आपस में सलाह करके अगली तिथि तय की गई वह कौन सी तिथि तय हुई और उसके बारे में मेरा पहला प्रश्न यह है, इसका जवाब देंगे तो दूसरा प्रश्न करूंगा?

SHRI M. M. JACOB; Sir, Mr. Sharma has asked a volley of questions in one question and has combined several aspects. The first part he was mentioning about the question

was that in the reply, weather condition was stated as one reason ana in another paragraph, the field situation was also stated as a reason. It is true that the weather conditions are a major factor in taking the census operation and there are instances in other States like Himachal Pradesh and some parts of Andaman and Nicobar islands. You take census not along with the other parts of India but at the same time,, non-synchronous dates are fixed and it is being held like that. If you see the way in which I answered the first part, in 1986-87, a non-synchfonous census was taken in this particular area and that was projected later. So this used to be held like that. The other part of his question is. under whose direction or with whose consultation, it was done ? In July 1988, the then Chief Minister of Jammu and Kashmir wrote a letter to the Prime Minister of India, stating that the State census should take place not in 1990-91 but if it is possible, at some other time. So it is always like that. So this is being done in consultation with the State Government whether it is possible or not. I mentioned about the field situation because as you know, during the census, workers will have to go to all parts of the field. For them to make an entry and get detailed investigation done, the situation is not conducive according to the State Government which is there this time. The State Government informed like this. So, this way, we have to find a suitable time.

Regarding the census final figures. there is not going to be any difficulty because we are proiecting it on the basis of a decennial census and we get a calculation.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : सभापति जी, जैसे कि मंत्री महोदय ने बताया हमारे इलैक्शंज होते हैं, इलैक्शज में भी कई बार पोलिंग पोस्टपोंड होती है. तो हिमाचल और जम्मू-कश्मीर दोनों के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर बर्फ पड़ती है तो वहां दोनों का इलैक्शन पोस्टपोंड होना है एक भी इलैक्शन ऐसा इस देश में नहीं हुआ जबकि सिर्फ श्रीनगर में इलैक्शन पोस्टपोंड हुआ हो और बाकी हिमाचल में यह कहीं पर नहीं पोस्टपोंड हुआ, जहां पर क्षेत्रीय परिस्थिति है, अगर क्षेत्रीय परिस्थिति काश्मीर में खराब है तो पंजाब में उससे भी बरस थी, लेकिन पंजाब में जनगणना हुई है और वहां पर काश्मीर को आपने नहीं की है। मैं समझता हूं कि न मौसम कारण है, न इसमें क्षेत्रीय परिस्थिति कारण है. जो बात सदन से छिपाई जाती है या छिपाई जा रही है मैं समझता हूं कि वहां पर कोई न कोई कंस्टीट्यूशनल या लीगल जिसको आर्टिकल 370 के अंतर्गत हम समझते हैं, कोई न कोई ऐसी अड़चन है कि आप स्टेट की अनुमति के बिना वहां कोई जनगणना भी नहीं कर सकते और ऐसे अनेक कानून है जो पार्लियामेंट भी पास करती है या देश में हम पास करते हैं, वहां लागू नहीं कर सकते तो मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि क्या सचमुच में कुछ क्षेत्रीय परिस्थिति, मौसम की परिस्थिति है या संवैधानिक दृष्टि से धारा 370 के कारण और प्रदेश ने इसमें कोई रुकावट डाली है और आपको उसके कारण से यह जनगणना रोकनी पड़ी है ?

SHRI M. M. JACOB: Sir, Artiele 370 is not a bar for holding census in Jammu and Kashmir. Census-was taken in Jammu and Kashmir in a different time. Article 370 is not a bar. It does not constitutionally prevent any of us to take census in Jammu and Kashmir.

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : शुरू में हमने सीज फायर किया। उसके बाद आर्टिकल-370 . . . (**व्यवधान**) . .

श्री सभापति : अब आप प्रश्न कर लो। यह समय खत्म हो रहा है।

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : चेयरमैन सर, मैं पूछ रहा हू, आर्टिकल 370 रख

के सेपरेट उसका हिस्सा रखा गया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार जम्मू-काश्मीर को देश के और नजदीक लाने के लिए, उसको एसीमिलेट करने के लिए, एक नेशन में शामिल करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

MR. CHAIRMAN; Question Hour i» over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाना

*225. श्री सत्य प्रकाश मालवीय: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली को राज्य का दर्जा दिये जाने के मुद्दे पर सरकार का मत क्या है; और

(ख) क्या सरकार इस संबंध में राजनैतिक दलों तथा जन-प्रतिनिधियों से परामर्श करने का विचार रखती है, और यदि हां, तो कब?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) और (ख) संविधान (72वां संशोधन विधेयक, 1990 को लोक सभा में 31-5-90 को प्रस्तुत किया गया। विधेयक के अनुसार संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को "दिल्ली राजधानी राज्य" के रूप में परिवर्तित करना था। विधेयक को 6-9-1990 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। लोक सभा के भंग हो जाने से विधेयक समाप्त हो गया।

इस विधेयक को पुन: प्रस्तुत करने का कोई तात्कालिक प्रस्ताव नहीं है।

NRI Status to people of Indian Origin in Israel

*226: SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of EXTERNAL AF-FAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that about 35,000 Israeli citizens of Indian origin qualify for the status of NRIs;

(b) whether it is a fact that Government is pursuing a discriminatory attitude towards Israel based NRIs in the issuance *of* visa; and

(c) whether there is any proposal to open an office in Israel for issuance of visas to NRIs in Israel to visit their relatives in India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) Israeli citizens of Indian origin are entitled to the same facilities as other foreign nationals of Indian origin including in the grant of visas.

(c) No, Sir.

Punjab Ultras in Uttar Pradesh

*227. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the various reports appearing in a section of the press that over 150 ultras of Punjab have sneaked into Uttar Pradesh;

(b) if so, the details in this regard;

(c) whether any measures have been taken to flush out these Ultras from Uttar Pradesh; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Government are aware of a press report, attributed to the Director General of U.P. Police, However, according to the Government of U.P. contradiction was issued the same day.